**DEPARTMENT OF POLTICAL SCIENCE**

**Dr. Shashwati**

**2018 – 19**

**Chapter - "Soochna Ka Adhikar" in an edited book by Dr.Urmil Vats and Dr. Preeti Chahal entitled "Humare Kanoon, Humare Adhikar". - JRS Publishing House LLP, New Delhi**

**ISBN 978-93-87684-08-9**

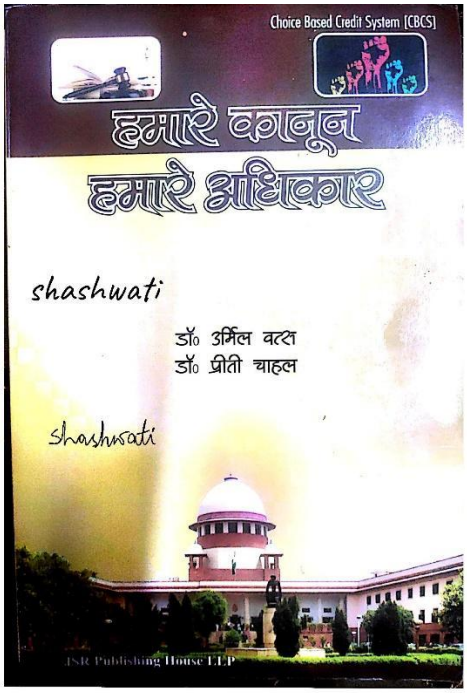


Scanned with CamScanner

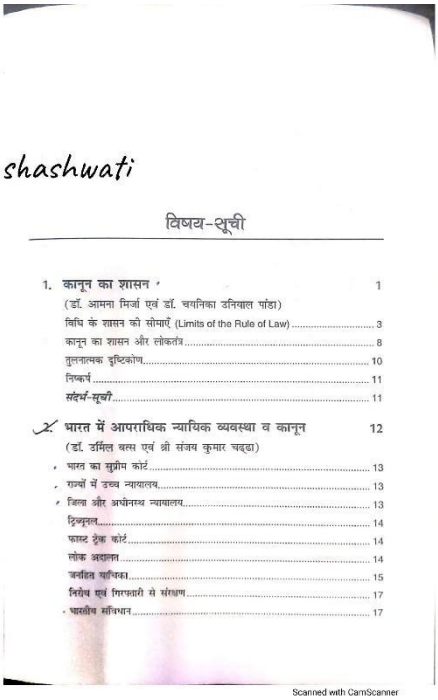

shashwati

विषय-सूची

1. कानून का शासन 1
(डॉ. आमना मिर्जा एवं डॉ. चगनिका उनियाल पांडा)
विधि के शासन की सीमाएँ (Limits of the Rule of Law) 3
कानून का शासन और लोकतंत्र 8
तुलनात्मक दृष्टिकोण 10
निष्कर्ष 11
संदर्भ-सूची 11

भारत में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था व कानून 12
(डॉ. उर्मिल वत्स एवं श्री संजय कुमार चड्ढा)
भारत का सुप्रीम कोर्ट 13
राज्यों में उच्च न्यायालय 13
जिला और अधीनस्थ न्यायालय 13
ट्रिब्यूनल 14
फास्ट ट्रैक कोर्ट 14
लोक अदालत 14
जनहित याचिका 15
गिरफ्तारी से संरक्षण 17
भारतीय संविधान 17

Scanned with CamScanner

shashwati



सांसदों विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई एक वर्ष में फैसले की जरूरत .......... 19
विधि आयोग की सिफारिशें .......... 20
नफरत फैलाने वाले भाषणों पर विधि आयोग दिशा-निर्देश तैयार करेगा .......... 20
आपराधिक मानहानि व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता .......... 21
पक्ष-विपक्ष .......... 23
प्रथम सूचना रिपोर्ट [First Information Report (FIR)] .......... 24
परिचय .......... 25
जीरो एफ.आई.आर. (ZERO FIR) .......... 25
प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रावधान .......... 26
एफ.आई.आर. एक महत्वपूर्ण सिद्धांत .......... 27
एफ.आई.आर. करवाते समय इन बातों का रखें ध्यान .......... 28
एफ.आई.आर. में दें यह जानकारी .......... 28
ऑनलाइन एफ.आई.आर. (Online FIR) .......... 28
सर्वोच्च न्यायालय ने बताया अनिवार्य .......... 29
एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करें, तो ये कर सकते हैं हम .......... 30
एफ.आई.आर. लिखने का 9K का फार्मूला .......... 30
अन्य जानकारी .......... 31
विचारण के बारे में-अभियुक्त के दृष्टिकोण से .......... 32
ट्रायल आरंभ होने पर अभियुक्त के दृष्टिकोण से .......... 35
किशोर अपराध .......... 37
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण .......... 39
नालसा के कार्य .......... 40
मुफ्त कानूनी सेवाएँ .......... 40
मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र .......... 40
*संदर्भ-सूची* .......... 41

shashwati

Scanned with CamScanner

shashwati

अध्याय-7

# सूचना का अधिकार

**शाश्वती**
सहायक प्रोफेसर,
राजनीतिक विज्ञान विभाग
माता सुंदरी कॉलेज फॉर वूमेन
दिल्ली विश्वविद्यालय

## भूमिका (Introduction)

जनसूचना के अधिकार को किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की पहचान के रूप में देखा जाता है। शासन व्यवस्था में जनसहभागिता का ऊँचा दर, स्वशासन और सुशासन का परिचायक है, और यह सुनिश्चित करने में सूचना के अधिकार का खासा महत्व है। नागरिकों की सूचना तक पहुँच न सिर्फ व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करती है, बल्कि लोक संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है, तथा सही मायने में, सहभागी लोकतंत्र की तरफ एक पुख्ता कदम है। आज के समय में शासक वर्गों और नागरिकों के बीच बढ़ती दूरी को खत्म करने, और सत्ता के केन्द्रीकरण को तोड़ने के लिए सूचना का अधिकार या राइट टू इंफोर्मेशन (आरटीआई) अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक जागरूक और जानकार नागरिकता ही सत्ता के निरंकुश इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है, और इसके लिए जनसूचना के अधिकार की बहुत अहमियत है।

भारत देश में सूचना के अधिकार के संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। 1990 के दशक को इस संघर्ष की शुरुआत माना गया जब सूचना के अधिकार की मांग को केन्द्र में रखकर एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे कानूनी और राजनैतिक, दोनों स्तरों पर मजबूती के साथ लड़ा गया। लेकिन इस संघर्ष की नींव इससे भी पहले पड़ चुकी थी। 1970 और 1980 के दशकों के कई महत्वपूर्ण आंदोलनों में, पर्यावरण, आजीविका, उचित वेतन इत्यादि प्रमुख मांगों के साथ, सरकारी कामों में पारदर्शिता और सूचना तक पहुँच की मांग को भी उठाया जा रहा

Scanned with CamScanner

shashwati

# हमारे कानून हमारे अधिकार

## पुस्तक के विषय में

दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के स्नातक कार्यक्रम [Choice Based Cred[illegible] (CBCS)] के पाठ्यक्रम, **'हमारे कानून, हमारे अधिकार'** पर लिखी गई यह पुस्तक एक [illegible] अकादमिक पहल है। कानूनी परिप्रेक्ष्य में अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के मध्य सामंजस्य [illegible] नागरिकों को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अग्रसर करने के लिए हिन्दी भाषा में लि[illegible] यह पुस्तक विद्यार्थियों व शिक्षार्थियों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। उक्त विषय [illegible] द्वारा विचारों का यह संकलन और प्रकटीकरण एक सृजनात्मक आरंभ है जो राज[illegible] ज्ञान विषय पर नव समाज को उत्कृष्टता की ओर अभिमुख करेगा।

## लेखक के विषय में

**डॉ. उर्मिल वत्स** दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में सह[illegible] सर के पद पर कार्यरत है। ये शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों से अपनी सेवाएँ दे रह[illegible] अनेक शोध राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रकाशित हो चुके [illegible] ational Women's Empowerment and Development Award, Awaited [illegible] ational Association of Educators for World Peace द्वारा सम्मानित किया गया [illegible] अधिकार भारतीय राजनीति और शासन व राजनीतिक सिद्धांत जैसे विषयों में इनकी [illegible] है।

**डॉ. प्रीति चाहल** दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज [illegible] फेसर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एम.फिल. और पी[illegible] है। इनकी प्रकाशित पुस्तके हैं: साहरावी रिफ्यूजी वेस्टर्न सहारा कॉन्फलिक्ट (दिल[illegible] इंटरनेशल पब्लिशिंग हाऊस, 2014) रिफ्यूजी एंड हास्ट स्टेट, (दिल्ली: विस्ता इंटरनेश[illegible] शिंग हाऊस, 2014) की लेखिका है। इसके अलावा ये दिल्ली विश्वविद्यालय के विकासशी[illegible] के अध्ययक्ष शोध केंद्र में फैलों के रूप में कार्य कर रही है। खासतौर पर गाँधी अध्ययन, साऊथ एशिया में शरणार्थी अध्ययन और महिलाओं से जुड़े वाद–विवादों पर इनकी विशेष रूचि है।

₹195/-
ISBN 978-93-87684-08-9

JSR Publishing House LLP
Corporate Office: WZ 61/8A, Vashisth Park,
Pankha Road, New Delhi-110046
Phone: 011-28520879, +91-9821497910
E-mail: sales@jsrfg.in; Website: http://www.jsrfg.in

Scanned with CamScanner